सार्वजनिक यातायात ज़रूरी है

भारत में बढ़ते शहरीकरण के साथ-साथ विभिन्न किस्म की यातायात सुविधाओं में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। यह देखा गया है कि शहरी यातायात में निजी वाहनों की संख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। सार्वजनिक यातायात के स्थान पर निजी वाहनों की वृद्धि का शहरों के पर्यावरण पर क्या असर होगा इसकी तुलना करंट साइन्स के एक ताज़ा अंक में की गई है। गौरतलब है कि शहरी यातायात कार्बन उत्सर्जन में एक बड़ा योगदान देता है और कई देशों में तो यह एकमात्र स्रोत है जिसके उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है।

भारत में 2001 से 2008 की सात वर्ष की अवधि में पंजीकृत वाहनों की संख्या दुगनी हो गई। इस वृद्धि के साथ कई समस्याएं भी पैदा हुई हैं। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में प्रतिदिन 3000 टन प्रदूषक हवा में पहुंचते हैं, जिसमें से एक-तिहाई वाहनों से निकलते हैं। इसी प्रकार से शहरी प्रदूषण में वाहनों का योगदान मुंबई में 52 प्रतिशत और कोलकाता में 33 प्रतिशत है।

सार्वजनिक यातायात की बात करें तो कोई बस 'स्वच्छ' हो या 'गंदी', वह कम से कम 5-50 छोटे दोपहिया, चार पहिया वाहनों का स्थान लेती है। कई बड़े शहरों में ये बसें अत्यंत प्रदूषणकारी स्कूटरों और मोटर सायकिलों को हटाती हैं। अर्थात बसों का उपयोग किया जाए, तो ईंधन की बचत होगी, कार्बन डाईऑक्साइड तथा अन्य प्रदूषक पदार्थों के उत्सर्जन में कमी आएगी।

ग्राफ में दिल्ली के 1990 के आंकड़े दर्शाए गए हैं और 2020 के लिए दो अलग-अलग परिदृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। आप देख ही सकते हैं कि यदि 75 प्रतिशत यातायात को बसों में लाया जा सके, और ये बसें लगभग पूरी भरी हों (60 यात्री) या यदि 40 प्रतिशत यातायात बसों से हो जो थोड़ी छोटी हों (35 यात्री) तो कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। ग्राफ से स्पष्ट है कि सार्वजनिक यातायात प्रणाली न सिर्फ कार्यक्षम होगी बल्कि इससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी। ***(स्रोत फीचर्स)***

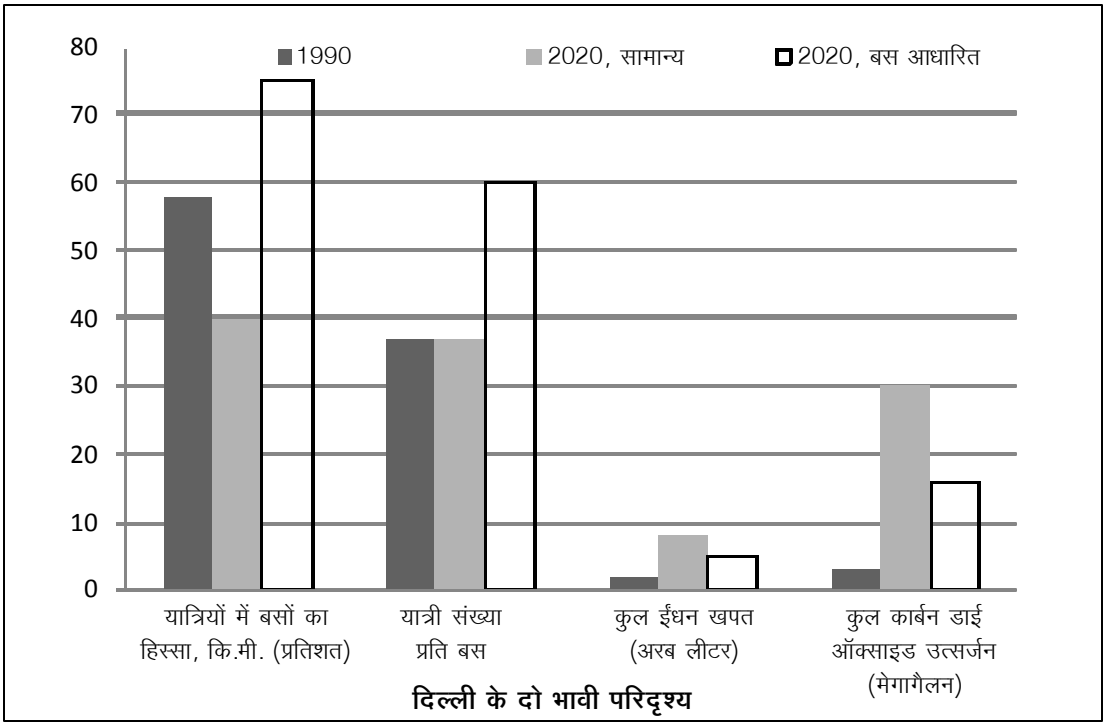

दिल्ली के दो भावी परिदृश्य